



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

शाधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 571]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 2, 1985/अग्रहायण 11, 1907

No. 571]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 2, 1985/AGRAHAYANA 11, 1907

इस भाग में भिन्न दृष्टि संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 1985

का. प्र. 873 (अ) -- केन्द्रीय सरकार ने भूतपूर्व कृषि और मिर्चाई  
मंत्रालय (खाद्य विभाग) द्वारा चीनी उपक्रम (प्रबंध प्रणाली) अध्यादेश  
1973 (1973 का 5) के धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (अ) के  
अधीन जारी किए गए अपने आदेश सं. का. प्र. 695 (अ) तारीख 1  
दिसम्बर, 1978 द्वारा घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश राज्य के मुरादाबाद  
जिले के राजा का सहनपुर स्थित अजुगुआ सुगर मिल्स का प्रबंध 2  
दिसम्बर, 1978 से तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार में  
निहित हो जाएगा, और उक्त निहित होने के अवधि चीनी उपक्रम (प्रबंध  
प्रणाली) अधिनियम, 1973 (1973 का 49) के धारा 3 के अधीन  
समय-समय पर जारी किए गए आदेशों, अर्थात् भारत सरकार के खाद्य  
और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (खाद्य विभाग) के आदेश सं. का. प्र.  
859 (अ) तारीख 1 दिसम्बर, 1981 का प्र. 882 (क) तारीख  
26 नवम्बर 1984 और का. प्र. सं. 206 (अ) तारीख 21 मार्च,  
1985 के अनुसार 1 दिसम्बर, 1985 तक बढ़ा दी गई थी।

1186 GI/85

(1)

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि उक्त चीनी उपक्रम का प्रबंध  
उनके ग्यामियों, को, जिनसे उक्त चीनी उपक्रम का प्रबंध ले लिया गया  
था, प्रत्यावर्तित कर देना समीचीन है,

और दिल्ली उच्च न्यायालय ने तारीख 8 अक्टूबर 1985 के अन्तरिम  
आदेश द्वारा, 1985 के सिविल वाद सं. 1918 में यह आदेश किया था  
कि प्रतिरक्षक, अन्तरिम आवेदन के निपटाए जाने तक कारखाने का कच्चा  
स्वामियों को नहीं सौंपेगा-

और उक्त अन्तरिम आदेश, माननीय उच्च न्यायालय ने 2 दिसम्बर  
1985 को खारिज कर दिया है-

अब केन्द्रीय सरकार, साधरण खंड अधिनियम, 1997 (1997 का  
10) की धारा 21 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा  
प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 2 दिसम्बर 1985 के साथ  
6.00 बजे में उक्त आदेश सं. का. प्र. 206 (अ) तारीख 21 मार्च,  
1985 के साथ पठित उक्त आदेश सं. का. प्र. 695 (अ) तारीख 1  
दिसम्बर, 1978 को विधिवत करती है।

[का. सं. 4-6/85-एन.एस.यू.]

डी. लक्ष्मी रत्न, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF FOOD &amp; CIVIL SUPPLIES

(Department of Food)

## ORDER

New Delhi, the 2nd December, 1985

S.O. 873(E).—Whereas by its order No. S.O. 695 (E), dated the 1st December, 1978, issued under clause (b) of sub-section (2) of section 3 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Ordinance, 1978 (5 of 1978), the Central Government in the erstwhile Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food), declared that the management of Ajudhia Sugar Mills at Raja-ka-Sahaspur, District Moradabad in the State of Uttar Pradesh, shall vest in the Central Government for a period of 3 years with effect from the 2nd December, 1978, and the period of the said vestment was extended from time to time up to the 1st December, 1985, vide orders of the Government of India in the Ministry of Food and Civil Supplies (Department of Food) No. S.O. 859 (E), dated the 1st December, 1981, S.O. No. 882(E), dated the 26th November, 1984, and S.O. No. 206 (E), dated the 21st March, 1985, issued under section 3 of the Sugar Undertakings (Taking Over of Management) Act, 1978 (49 of 1978);

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient that the management of the said sugar undertaking should be restored to the owners from whom the management of the said sugar undertaking was taken over;

And whereas the High Court of Delhi by an interim Order dated 8th October, 1985, in Civil Suit No. 1918 of 1985 ordered that the Custodian shall not hand over possession of the factory to the owners pending disposal of the Interim Application;

And whereas the said Interim Application has been dismissed by the Hon'ble High Court on 2nd December, 1985;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the Central Government hereby rescind the said order No. S.O. 695 (E), dated the 1st December, 1978 read with the said order No. S.O. 206 (E), dated the 21st March, 1985, with effect from 18.00 hour of the 2nd December, 1985.

[F. No. 4-6185-NSU]

V. LAKSHMI RATAN, Jt. Secy